शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 16-10-2020, वर्ग - BA-III

प्रश्न :- संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशुल्क - नीति का संक्षिप्त विवरण दीजिये।

उत्तर :- 1844 के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था अवसाद से मुक्त हो गई। 1845 में डेमोक्रेटिक दल सत्ता में आया, जो नीचे प्रशुल्कों का समर्थक था। अतः 1846 में 'वॉकर प्रशुल्क अधिनियम' पारित हुआ। इसके अन्तर्गत आयातित वस्तुओं को तीन श्रेणियों में बाँटा गया तथा प्रत्येक श्रेणी के वस्तुओं के लिए प्रशुल्क की अलग दर निश्चित की गई। विलास वस्तुओं पर 100 प्रतिशत तथा अर्धविलास वस्तुओं पर 50 प्रतिशत प्रशुल्क लगाया गया। वाणिज्यिक वस्तुओं के लिए प्रशुल्क की दरें 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक निर्धारित की गई। इस व्यवस्था का सरकारी ~~व्यय~~ आय पर अनुकूल प्रभाव पड़ा तथा अमेरिकी अर्थव्यवस्था समृद्धि की ओर अग्रसर हुई। बाद में 1857 के प्रशुल्क अधिनियम द्वारा सभी स्तरों पर प्रशुल्क की दरों में 5 प्रतिशत की कमी की गई तथा प्रशुल्क रहित आयात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ाई गई।

उच्च प्रशुल्को की अवधि — 1857 के पश्चात अमेरिका को पुनः आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। गृह युद्ध के कारण सरकार की आर्थिक कठिनाईयाँ अधिक बढ़ गयी है। अतः "प्रत्येक वस्तुओं पर करारोपण" का नारा पुनः प्रचलित हो गया। ~~युद्ध~~ गृह-युद्ध के समय (1861-65) अमेरिकी सीनेट में केवल उत्तरी राज्यों का प्रतिनिधित्व था, जो ऊँचे संरक्षणात्मक प्रशुल्कों के समर्थक थे। अतः प्रशुल्क दरों में भारी वृद्धि की गयी। सर्वप्रथम 1861 को 'मोरिल प्रशुल्क अधिनियम' के अन्तर्गत आयातित वस्तुओं पर मूल्यानुसार करों की जगह विशिष्ट कर लगाए गए तथा आयात शुल्कों में इतनी वृद्धि की गयी कि वे 1846 के वाकर प्रशुल्क अधिनियम के बराबर हो गए। तदुपरान्त 1864 के प्रशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सभी वस्तुओं पर प्रशुल्क की दरें बढ़ा दी गयी। प्रशुल्क की औसत दर 47 प्रतिशत हो गयी। गृह-युद्ध के समाप्ति पर उत्पादन-शुल्क बराबर

गए किन्तु प्रशुल्क की दरें पूर्ववत ऊँची बनी रहीं। परिणामतः व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो गयी तथा 'उच्च संरक्षणात्मक प्रशुल्क' आलोचना का विषय बन गया। 1870 में प्रशुल्क की दरें कुछ घटायी गई। 1872 में सभी प्रकार की वस्तुओं पर प्रशुल्क की दरें 10 प्रतिशत घटा दी गई। चाय और कहवा जैसी वस्तुओं पर आयातशुल्क पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।

1873 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पुनः अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः 1875 में प्रशुल्क की दरें पुनः बढ़ाई गई तथा 1872 का प्रशुल्क अधिनियम रद्द कर दिया गया। 1881 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था अवसाद की स्थिति से उबर चुकी थी। अतः प्रशुल्क के प्रश्न पर विचार करने के लिए 1882 में एक आयोग गठित किया गया। आयोग ने प्रशुल्क दरों में 25 प्रतिशत की कमी का सुझाव दिया, किन्तु 1883 के अधिनियम द्वारा प्रशुल्क दरों में केवल 5 प्रतिशत तक कमी हो पाई।

1890 के मैक-किनले प्रशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सभी आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क

की दरें बढ़ाई गई। प्रशुल्क की औसत दर 48.4 प्रतिशत हो गई। अधिनियम के अन्तर्गत कृषि-वस्तुओं को भी संरक्षण प्रदान किया गया। राष्ट्रपति को कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने का अधिकार भी दिया गया। 1894 के 'विल्सन गोरमैन अधिनियम' के अन्तर्गत प्रशुल्क की औसत दर घटाकर 41.3 प्रतिशत कर दी गयी थी। किन्तु 1897 के 'डिंगले प्रशुल्क अधिनियम' के अन्तर्गत प्रशुल्क की औसत दर बढ़ाकर 57% कर दी गयी। 'डिंगले अधिनियम' पर आधारित प्रशुल्क नीति लगभग 12 वर्षों तक चली। इस अवधि में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ।